व्यापारी वर्ग अभी भी जीएसटी के लागू होने से डरा हुआ

करनाल (जे के: पी के) पूरा व्यापारी वर्ग अभी जी एस टी के लागू होने से डरा हुआ था। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने उसका भी जुगाड़ कर लिया है तथा व्यापारियों को हिस्सा देने के बदले व्यापार का स्वरूप ही बदल दिया। पूरे सिस्टम में इतनी पारदर्शिता है कि कहीं गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं दिखती।

बिना बिल काटे कोई भी सामान बेचना या खरीदना कानूनी जुर्म है पर यह अपराध शहर में प्रतिदिन रोजाना हो रहा है। छोटा हो या बड़ा अधिकारी टैक्स की चोरी करने के लिये ग्राहक को बिल रसीद नहीं काट कर देते। जिसके चलते सरकार को लाखों रुपये के राजस्व को चूना लगा रहा है। शहर में सैंकड़ों छोटे व बड़े करोबार संचालित के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सदर बाजार में जूता बनाने के भी कई कारखाने चल रहे हैं। यहां 90 प्रतिशत व्यापारी टैक्स छिपाने के लिये ग्राहकों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को पक्की रसीद नहीं देते। वे टैक्स चोरी कर न सिर्फ़ उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं अपितु सरकार को मिलने वाले राजस्व को भी भारी चूना लगा रहे हैं।

खासतौर पर कृषि उत्पाद, इलैक्ट्रोनिक्स, कपड़ा, ईट भट्ठा और छड़-सीमेंट व रेत मिट्टी जूता बेचने वाले व्यापारी, क्रय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सभी ऐसे व्यवसाय है जहां करोड़ों रुपये के उत्पादों की बिक्री होती है। रुपये लेकर सामान तो उपलब्ध करवा दिया जाता है और कारोबारी सरकारी टैक्स के नाम पर उत्पादों का ऊंचा दाम वसूलते हैं। जबकि खरीददारों को इसकी पक्की रसीद भी नहीं दी जाती। यदि कोई जागरूक उपभोक्ता दुकानदारों से रसीद मांगी जाती है तो ना नुकर कर दिया जाता है।

बिना रसीद करोबार करने वाले व्यापारी खुले आम टैक्स चोरी करते हैं। यहां कई दुकानदार ऐसे भी है, जहां पर ग्राहक चाहे कोई भी उत्पाद खरीदे उससे उत्पाद में लिखे अंकित मूल्य से भी अधिक कीमत वसूली जाती है। जब ग्राहक इस बारे में पूछता है तो उसे कह दिया जाता है कि अधिक वसूली की गई राशि जी एस टी की राशि है। परन्तु दुकानदार जानबूझकर उसकी रसीद भी नहीं देता। और जल्दबाजी के फ़ेर में ग्राहक भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि पक्का बिल या रसीद ही नहीं दी तो फ़िर टैक्स कैसा। या कभी ग्राहक सोचता है कि मैं रसीद का क्या करूंगा।

त्योहारी सीजन व संडे बाजार में अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सेल लगाते हैं। जहां उत्पादों को सस्ता बता कर तय दाम में बेचा जाता है। लुभावने स्कीम के चक्कर में फंसकर लोग खूब रुपये लुटाते हैं। वास्तव में यह टैक्स से बचने के लिये दुकानदारी की सोची-समझी चाल होती है। ऐसे दुकानों में ऑफ़र के नाम पर ग्राहकों को खूब लूटा जाता है। किसी भी उत्पाद के बदले राशि तो पूरी ली जाती है लेकिन कच्चा बिल थमा दिया जाता है। जागरूकता के अभाव में लोग ठगे जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि टैक्स चोरी का धन्धा कराधान विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के बिना नहीं चल सकता। उनकी सैटिंग होती है तभी व्यापारी 2 नं. का करोबार करते हैं। ट्रांसपोटरों ने तो कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी मंथली बांध ही रखी है इसलिये अधिकारी आंखे बन्द करके रखते हैं। बता दें कि व्यापारी जब सेल टैक्स विभाग में पूरे साल की असेस्मेंट करवाने जाता है तो उसकी कमियों को नज़र अंदाज करने की फ़ीस लिये बिना केस नहीं करते। सूत्रों के मुताबिक कम से कम और छोटा से छोटा भी केस हो तो उसके लिये तीन हज़ार फ़ीस है इसके बिना केस को हाथ भी नहीं लगाते।

सदर बाजार, जवाहर मार्केट में जूतों का करोबार धड़ल्ले से 2 नम्बर में चल रहा है। यहां से जूता सहारनपुर, मुजफ़्फ़रनगर, हिमाचल, व दिल्ली में बेचा जाता है और दिल्ली से जूता और रॉ मैटिरीयल आता भी है। थोक में जूते सप्लाई करने वाले विक्रेता क्रेता व्यापारी को माल पहुंचाने के बाद बिल वापिस लाकर टैक्स की चोरी की जा रही है। बता दें कि एक समाज सेवी ने इन्फोंसमैन्ट सेल टैक्स अधिकारी सतीश कुमार को सूचना दी कि जवाहर मार्कीट में दो नम्बर का माल उतर रहा है, आ कर चेक करें, तो उन्होंने असमर्थता जताते हुए कहा कि मैं बाहर हूं नहीं आ सकता।

अगर अधिकारी चाहता तो अपने विभाग के किसी अन्य अधिकारी को भेज कर छापा मार कर पकड़ सकता था। परन्तु ऐसा क्यों करता। जाहिर है सेटिंग के चलते टालना जरूरी था।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्क़त हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

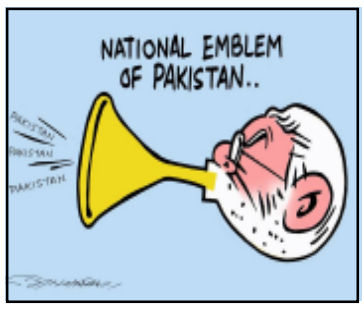

मंझावली पुल: कृष्णपाल का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ ध्वस्त

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 24-30 मार्च 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, साहित्यिक व आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। जब से मोदी सरकार केन्द्र में सत्ता में आई है तब से हिन्दूवादी अभियुक्तों के विरुद्ध दायर मुकदमों में जांच एजेंसियों व अभियोजन पक्ष को प्रभावित करके मुकदमों को कमज़ोर कर दिया जाता है जिससे वे अदालत में सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। हैदराबाद में मक्का मस्जिद (2007), अजमेर दरगाह (2007), समझौता एक्सप्रेस (2007) तथा मालेगांव (2006) धमाकों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व अन्य हिन्दूवादी संगठनों से संबंधित कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेन्द्र चौधरी आदि को इन धमाकों में लिप्त होने के प्रमाणों के आधार पर आरोपित बनाया गया था। जांच दल के लोग आरएसएस सदस्य जोशी से पूछताछ कर पाते उससे पहले ही जोशी की हत्या कर दी गई। तीन अन्य आरोपियों -रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे और अमित को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। हैदराबाद मक्का मस्जिद, मालेगांव तथा अजमेर शरीफ़ धमाकों में आरोपित व्यक्ति अदालतों से सबूतों के अभाव में समझौता एक्सप्रेस धमाके में भी बरी हो गये।

'जांच कर्ताओं की नज़र में समझौता धमाके से बिल्कुल साफ़ जुड़ता था हिंदुत्व समूहों का लिंक' में समझौता एक्सप्रेस धमाके के मुख्य जांच कर्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी विकास नायायण राय की रिपोर्ट के माध्यम से इन धमाकों में आरएसएस व अन्य हिन्दुत्ववादी संगठनों के हाथ होने का बेबाक खुलासा किया गया है। मालेगांव धमाके केस की सरकारी वकील रोहली सालियाना ने 2015 में एनआईए डायरेक्टर शरद कुमार पर हिंदू आतंकवादियों के प्रति नरमी से पेश आने के लिये उनके ऊपर दबाव डालने का आरोप लगाया था। इसी प्रकार का आरोप कुछ सेवानिवृत नौकरशाहों ने भी एनआईए प्रमुख पर लगाया गया था कि 2006 से 2008 के बीच हुए धमाकों की श्रंखला में हिंदू आतंकवादियों की भूमिका से लोग़ों का ध्यान भटकाया जा सके। स्पष्ट है कि एनआईए प्रमुख शरद कुमार सत्ता में बैठे हुए उच्चतम अधिकारी अथवा उच्चतम शासक के निर्देशों पर ही इन मामलों में हस्तक्षेप कर रहा होगा। अब गुजरात की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने सीबीआई को सेवानिवृत पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा तथा एन के अमीन के विरुद्ध इशरत जहां फ़र्जी मुठभेड़ मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर के खिलाफ़ धोखाधड़ी के मामले में बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज हस्ती व उद्योगपति अंबानी के करीबी के वी कामथ तथा अन्य को पूछताछ करने के लिये सीबीआई द्वारा नामजद करने पर विदेश में बैठे अरुण जेटली भड़क उठे और ब्लॉग लिखकर सीबीआई को निशाने पर ले लिया था। स्पष्ट है कि मोदी सरकार व जेटली अपनों के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार ही नहीं मानती। इतना ही नहीं किसी अन्य पार्टी का भ्रष्टाचार आरोपी सीबीआई आदि द्वारा पकड़े जाने पर भाजपा में आ जाता है तो वह पवित्र हो जाता है।

न्यूज़ीलैंड की दो मस्जिदों में आस्ट्रेलियन हत्यारे द्वारा 50 से अधिक नमाज़ियों की हत्या करने पर वहां की प्रधानमंत्री अर्डन काला लिबास पहने और सिर पर दुप्पटा लिये अपने नागरिकों को सुरक्षा न दे सकने पर क्षमा याचना करने व भरोसा दिलाने के लिये मुसलमानों के बीच गई जो किसी का भी दिल जीतने के लिये काफ़ी है। जबकि हमारे भारत में पुलवामा में आत्मघाती आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ़ के 44 जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मोड़ में आ गये और "**मैं देश नहीं झुकने दूंगा**" का गान करने और न्यूज़लैंड में मरे अपने 9 नागरिकों के प्रति कोई संवेदना प्रकट करने की बजाए उसे वोट के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। 'मौत का सौदागर!' तथा 'साबित हुआ मोदी एक मिस्टेक है!' से दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मानसिकता, सोच और कार्यशैली के बीच भारी अंतर उज़ागर होता है। न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री अपने देश के पीड़ित परिजनों से उनकी सुरक्षा न कर पाने के कारण माफ़ी मांग रही थी, तो भारतीय प्रधानमंत्री देश में युद्ध उन्माद फ़ैलाने और साम्प्रदायिक विद्वेष व तनाव बढ़ाने में लगे रहे।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गंगा नदी का संरक्षण, स्वच्छता और कायाकल्प के लिये बनाए गए 20 हज़ार करोड़ के नमामि गंगा प्रोजेक्ट की असफ़लता का 'मोदी का नमामि गंगे प्रोजेक्ट फ़ेल, 5 साल में सबसे खतरनाक स्तर पर प्रदूषण' में सटीक विश्लेषण किया गया है। विशेष ध्यान देने योग्य है कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित कमेटी के प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री मोदी है तथा इस कमेटी की आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है।

'मंझावली पुल: कृष्णपाल का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ ध्वस्त' में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर तथा मंझावली पुल बनाने के झूठे वादे से जनता को बेवकूफ़ बनाने के प्रयास का कचचा चिट्ठा खोला गया है।

'आत्म हनन के पथ पर मोदी!' में 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के लिये उत्तरदायी सामाजिक-राजनीतिक परिघटना तथा मोदी सरकार की योजनाओं व असफ़ल कार्यों जैसे नोटबंदी, विवादित रफ़ाल करार संवैधानिक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सीबीआई, एन आई ए आदि में मोदी-शाह के बेजा हस्तक्षेप की सटीक समीक्षा की गई है। पुलवामा हमले में जवानों की शहादत व बालाकोट प्रकरण के संदर्भ में मीडिया की मदद से मोदी जी 'राष्ट्रवाद' का उन्माद पैदा करके साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में कहा था कि मैं देश के धन का चौकीदार हूं। इसलिये रॉफेल करार में हुई अनियमितताओं को मोदी सरकार के खिलाफ़ सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नारा गढ लिया था-'चौकीदार चोर है'। यह मामला जोर पकड़ने लगा तो नारा गढ़ने में माहिर मोदीजी ने '**मैं भी चौकीदार**' अभियान चला दिया और उनकी देखा-देखी भाजपा के लगभग सारे केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया खाते में अपने नाम से पहले 'चौकीदार लगा लिया, जिसकी 'जनता को जिम्मेदार सरकार चुननी है, चौकीदार नहीं!' में चर्चा की गई है। वास्तव में मोदी जी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिये 'मैं भी चौकीदार' अभियान चला रहे हैं जैसे कि 2019 का लोकसभा चुनाव जिम्मेदार सरकार चुनने के लिये नहीं बल्कि चौकीदार चुनने के लिए है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी सरकार, भाजपा तथा आरएसएस सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में अपनी सफ़लता का खोखला दावा लगातार करते रहते हैं। वे अपने लोग़ों के भ्रष्टाचार को तो नज़रअंदाज कर ही देते हैं, परंतु विपक्ष के मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही ईडी, सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों को पीछे लगाने में कोई देरी नहीं लगाते। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की डायरी सामने आने से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसका येदियुरप्पा की डायरी में खुलासा:सीएम बनने के लिये दी थी जेटली, गडकरी और राजनाथ को करोड़ों रुपयों की रिश्वत' में भंडा-फ़ोड़ किया गया है। इस डायरी में स्वयं येदियुरप्पा के हाथ से इन्दराज किया गया है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के लिये येदियुरप्पा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, जजों तथा वकीलों को 1800 करोड़ रुपये दिए थे। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह डायरी केंद्रीय वित्तमंत्री तथा कर्नाटक प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण जेटली को एक बिना हस्ताक्षर वाले कवर नोट के साथ सौंपी थी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने के औचित्य के बारे में पूछा था, परंतु जेटली ने उस नोट पर कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान रहे कि आयकर विभाग और मोदी सरकार के पास इस डायरी की कॉपी अगस्त 2017 से ही है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है।

महान क्रांतिकारी भगत सिंह के शहीदी दिवस (23 मार्च) पर 'भगत सिंह और क्रांति यानी इंकलाब' के जरिये भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यक्रम से पाठकों को रूबरू कराने का सराहनीय कार्य किया गया है। जबकि आजकल लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु भगत सिंह का नाम तो लेते हैं, परंतु उनकी विचारधारा से उनका कोई सरोकार नहीं होता। प्रधानमंत्री द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में चायवाला तथा 2019 में मैं भी चौकीदार अभियान चलाने पर '2014-2019' तथा 'वक्त-वक्त की बात है पिछले चुनाव में मैं ब्रांड एम्बेसेडर था इस बार तुम ...-चायवाला-मैं भी चौकीदार कैंपेन' और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दे व मैं भी चौकीदार अभियान पर 'हम क्या चाहें? चौकीदार!' कार्टूनों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति पर उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।